AISA

11.2.06

On 9th February Incident in JNU:

Condemn Manufacturing of Lies to Malign JNU and Progressive Forces by ABVP and Some Media Houses!

Condemn Politically Motivated Divisive and Reactionary Sloganeering in the Name of Left!

The ABVP and some media houses are in an all out attempt to malign JNU and left-progressive organisations by spreading mis-information about a program on 9th February in JNU. At a time when the anti-national, anti-student and anti-people character of the BJP and ABVP have been exposed to the people of this country, this is an age old tactics by these forces to hide their real character.

Condemn the Reactionary Divisive Sloganeering: On 9th of February some students held a program named 'A Country Without Post Office'. It is important to mention here that AISA was not an organiser of the program, unlike what is being spread by ABVP and some media. While the poster of the program mentioned that it is being held on death anniversary of Afzal Guru, some slogans raised in the program were extremely divisive and reactionary and have nothing to do with concerns raised by a large section of civil society on capital punishment, or on the unanswered questions about the Parliament Attack case. Slogans like *'Bharat ke Tukde Honge Hazar'* were raised in the program. **AISA outrightly condemns such reactionary slogans.** Such sloganeering is shameful and a misuse of our hard won democratic space, painstakingly fought for by the left and democratic forces of the campus, and must not be tolerated. We believe such slogans and ideas have no place in the left and democratic movement. The left and democratic forces are the most consistent ones to defend the country and unity of its people against fundamentalist, majoritarian, casteist and anti-people forces. It is this unity of people of India as has been seen in recent times, that has challenged various autocratic and anti-people policies of the BJP government and the ABVP. That is why such slogans are not only condemnable and shameful but the political intentions of such sloganeering are highly questionable, since they only provide fodder for a discredited force like ABVP. During the program along with AISA activists several common students of JNU also opposed and stopped such sloganeering.

Some of the facts related to the program must be stated clearly. Some students organised the program. The administration at the end moment cancelled the already given permission under ABVP's pressure. But the organisers decided to go ahead with the program as declared. The ABVP not only played a role in cancelling the permission using administrative power, it was also present at the spot in full force to physically stop the program and create violence. It was in this backdrop that AISA along with several left and democratic organisations as well as common students were present at the spot to stop any kind of violence or vandalism. In this chaos, the provocative and reactionary slogans were given by some who are not associated with organisations like AISA. In fact such provocative sloganeering were opposed and stopped by AISA as well as various other progressive students.

However, ABVP's continuous vandalism, using administrative and state machinery, as seen that day is nothing new. The ABVP's role that day once again brings out their habitual tactics to create vandalism and spread flared up tension through the media. It is the ABVP which had physically stopped screening of *Muzaffarnagar Baqi Hai* from HCU to DU. Even in JNU, the ABVP got into physical violence when the film *Caste On The Menu Card* was being screened. They have also targeted minority students in JNU without any provocation during India-Pakistan cricket match. **From HCU to Delhi the ABVP has used state and administrative power to clamp down on any voice which is different from them, rather than engaging into debate.** It is the same ABVP that used the office of the MHRD and HCU administration to punish students like Rohith Vemula and his friends. That time too, they had tried hard to use the anti-national card against Rohith and his friends.

As far as the question of hanging of Afzal Guru is concerned, a large section of civil society, writers, well known lawyers and democratic forces have raised concern over capital punishment and its selective execution. Even PDP, the BJP's ally in J&K have raised questions over execution of Afzal Guru- before their alliance with BJP in 2013. (http://www.rediff.com/news/report/disappointed-at-the-hanging-of-afzal-guru-says-pdp/20130209.htm), as well as after the alliance in 2015 (http://indianexpress.com/article/india/politics/after-sayeeds-pak-remark-pdp-now-demands-return-of-afzal-gurus-mortal-remains/). **Yet, the BJP has no problem in running a government in J&K itself with the PDP. ABVP's opportunism is clear, they have no problem in BJP's running a government with PDP, however they would silence every differing voice using administrative and state power in campuses.** The ABVP's habit of suppressing all differing opinions by branding them as 'anti-national' must be resisted and the space for democratic debate and discussion must be safeguarded.

PTO for Hindi

Shweta Raj, President, AISA, JNU

Vijay Kumar, Gen. Secy, AISA, JNU

AISA

एबीवीपी और कुछ मीडिया घरानों द्वारा झूठ फैलाने व जेएनयू की छवि खराब करने की कोशिशें निंदनीय हैं.

9 फरवरी के कार्यक्रम में राजनीतिक रूप से प्रेरित, विभाजनकारी और प्रतिक्रियावादी नारेबाजी की हम निंदा करते हैं.

एबीवीपी और कुछ मीडिया घराने जेएनयू के वाम-प्रगतिशील संगठनों की छवि खराब करने के लिए झूठ फैलाने में लगे हुए हैं यह पूरा अभियान 9 फरवरी को कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में संचालित है. जब-जब भाजपा और एबीवीपी का राष्ट्र-विरोधी, छात्र-विरोधी, जन-विरोधी चरित्र उजागर होता है, तब-तब अपने असली चरित्र को छिपाने के लिए ये इसी तरह के कर्मों में लिप्त होते हैं.

प्रतिक्रियावादी और विभाजनकारी नारेबाजी की निंदा : 9 फरवरी को कुछ छात्रों ने 'कंट्री विदआउट पोस्ट ऑफिस' नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया था. यहां **यह साफ किया जाना जरूरी है कि आइसा इस कार्यक्रम का आयोजक नहीं था, जैसा कि एबीवीपी और कुछ मीडिया चैनलें द्वारा फैलाया जा रहा है.** कार्यक्रम के पोस्टर में इस बात का उल्लेख था कि यह कार्यक्रम अफ़ज़ल गुरू के मृत्यु दिवस पर आयोजित है. इस कार्यक्रम में लगे कुछ नारे अत्यंत विभाजनकारी और प्रतिक्रियावादी थे. इन नारों का व्यापक नागरिक समुदाय द्वारा मृत्युदंड पर उठाये गये सवाल और संसद हमले के अनुत्तरित प्रश्नों से कोई वास्ता नहीं है. कार्यक्रम में 'भारत के टुकड़े होंगे हजार' जैसे नारे लगाये गये. **आइसा ऐसे नारों की तीखी भर्त्सना और निंदा करता है.** हमारा मानना है कि वाम-लोकतांत्रिक आंदोलनों में ऐसे विचारों और नारों के लिए कोई जगह नहीं है. बल्कि दूसरी तरफ वाम-लोकतांत्रिक ताकतें रूढ़िवादी, बहुसंख्यकवादी, जातिवादी ताकतों के खिलाफ देश के लोगों की एकजुटता के लिए संघर्ष करती रही हैं. हाल के दिनों में भारत के लोगों की इसी एकजुटता ने भाजपा और एबीवीपी की जनविरोधी और तानाशाही नीतियों का विरोध किया. **इसीलिए ऐसे नारे न सिर्फ निंदनीय हैं, बल्कि ऐसी नारेबाजी की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है.** ऐसी नारेबाजी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी एबीवीपी जैसी ताकतों को ऑक्सीजन देने का काम करती है. आइसा कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य छात्रों ने भी ऐसी नारेबाजी का विरोध किया और इसे रोकने की कोशिश की.

इस दौरान एबीवीपी ने जिस तरह से उत्पात और उन्माद खड़ा किया वह देश भर में उनकी झूठ घृणा और उन्माद की राजनीति का ही एक नमूना भर था. भाजपा की सरकार बनने के बाद मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई से लेकर लखनऊ, इलाहबाद और दिल्ली तक ये लोग प्रशासन, सरकार और पुलिस के सहारे किस तरह लोकतान्त्रिक मांगों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चढ़ बैठे हैं, इसे हम सबने देखा है. केन्द्रीय मंत्रियों और विश्विद्यालय के वीसी के जरिये इनलोगों ने कुचक्र रचकर रोहित वेमुला को आत्महत्या की ओर धकेल दिया. सामजिक न्याय, लोकतंत्र और असहमत होने के अधिकार पर जिस तरह संघब्रिगेड ने हमला तेज़ किया है, वह हम सबके लिए एक चुनौती है.

जेएनयू में इससे पहले भी 'मुजफ्फरनगर बाकी है' फिल्म दिखाने के दौरान इन्होंने उत्पात मचाया था. 'कास्ट ऑन द मेनू कार्ड' फिल्म दिखाने के विरोध में उनका हंगामा और गुंडागर्दी को हमलोगों ने देखा ही है. कई बार भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान इनलोगों ने कश्मीरी और अल्पसंख्यक छात्रों पर हमले किये हैं. इन्होंने जेएनयू में कई पब्लिक मीटिंग व अन्य कार्यक्रमों के दौरान तोड़-फोड़ और हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया है और इन सभी घटनाओं में पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर ये लोग असहमति और विरोध के स्वर को दबाने की भरपूर कोशिश करते हैं.

जहाँ तक अफ़ज़ल गुरु का मामला है तो उसकी फांसी और इस पूरे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर देश के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पत्रकारों और लेखकों ने सवाल खड़े किए है. यहाँ तक कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा के सहयोगी दल पीडीपी और इसके कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किये हैं. गठबंधन से पहले भी (2013) (http://www.rediff.com/news/report/disappointed-at-the-hanging-of-afzal-guru-says-pdp/20130209.htm), और गठबंधन के बाद भी(2015) http://indianexpress.com/article/india/politics/after-sayeeds-pak-remark-pdp-now-demands-return-of-afzal-gurus-mortal-remains/ इसके बावजूद भी बीजेपी अभी तक उनके साथ ख़ुशी-ख़ुशी जम्मू-कश्मीर में सरकार चला रही थी और आगे भी चलाने के लिए लालायित है. अगर अफ़ज़ल की फांसी पर सवाल उठाना ही 'देशद्रोही' हो जाना है तो क्या भाजपा एक 'देशद्रोही' पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है?

अफ़ज़ल गुरु की फांसी को लेकर मुख्यधारा की कई पत्रिकाओं में आलोचनाएँ छपी हैं, स्वतन्त्र किताबें छपी हैं. कई विद्वानों, कानूनविदों द्वारा सवाल उठाये गए हैं. मिसाल के तौर पर - http://www.openthemagazine.com/article/nation/the-question-of-reasonable-doubt अब सवाल उठाने वालों को गालियां देकर, उन्हें 'देशद्रोही' कहकर या उनकी आवाज़ दबाकर हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते. उन सवालों से संवाद स्थापित कर तथा उनका जायज़ हल ढूंढ कर ही हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की तरफ बढ़ पाएंगे जो लोग इस मामले पर यह कहकर आवाजों और सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि 'यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था' उनकी त्रासदी देखिये कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब डीयू के प्रोफेसर एसएआर गिलानी को बरी कर दिया है तब भी आये दिन एबीवीपी के लोग उनपर हमला करते हैं . अभी हाल में ही जेएनयू में हुई एक पब्लिक मीटिंग में उनपर पत्थर फेंके गए, 'देशद्रोही' कहकर उन्हें गालियाँ दी गयीं .

असल मामला यह है कि एबीवीपी को अपनी उन्मादी और गुंडागर्दी की राजनीति के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए. वे असहमति के हर स्वर को दबा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. दूसरी ओर, उस कार्यक्रम में 'भारत की बर्बादी' का नारा देने वाले भी पिछले दरवाजे से एबीवीपी की मदद ही कर रहे हैं. एक उन्मादी कट्टरता को दूसरे उन्मादी कट्टरता से नहीं रोका जा सकता है.

आज ज़रूरत है कैम्पसों और समाज में वाद-विवाद, असहमति और सवाल खड़ा करने की संस्कृति को और अधिक मजबूत करने की लोकतंत्र की रक्षा और उसे जनवादी स्वरूप देने के लिए एकजुटता की- साथ ही झूठ, उन्माद और घृणा फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ एक व्यापक एकता और मुकम्मल प्रतिरोध खड़ा करने की.

PTO for English

Shweta Raj, President, AISA, JNU

Vijay Kumar, Gen. Secy, AISA, JNU